सुब्रमनिया गौंडन

बनाम

मद्रास राज्य

(बी. पी. सिन्हा, गोविंदा मेनन और जे. एल. कपूर, जे. जे.)

आपराधिक कानून-वापस लिया गया स्वीकारोक्ति-पुष्टि, मजिस्ट्रेट को दर्ज करके प्रश्न की आवश्यकता-यदि कोई प्रलोभन हो।

अपीलार्थी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ चश्मदीद गवाहों पर भरोसा नहीं किया गया था। उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी से पूछे गए प्रश्नों में से एक थाः "आप किस उद्देश्य के लिए बयान देने जा रहे हैं?" इस पर उन्होंने जवाब दिया, "हत्या के मामले में दूसरों को फंसाया जाएगा, मैंने अकेले हत्या की है।" यह तर्क दिया गया था कि जिस तरीके से सवाल पूछा गया था, उससे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रलोभन दिया गया था। हत्या के अगले दिन "एक दराज, एक बनियान और एक चादर", सभी मानव रक्त से सना हुआ अपीलार्थी से बरामद किया गया, जिसके लिए उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सत्र न्यायालय के समक्ष स्वीकारोक्ति को वापस ले लिया गया। इन बरामदगी का उपयोग स्वीकारोक्ति की पुष्टि के रूप में किया गया था। यह तर्क दिया गया कि यह कोई पुष्टि नहीं थी।

माना गया कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी और मजिस्ट्रेट द्वारा एक पूरी तरह से हानिरहित प्रश्न रखना, जो मद्रास क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस द्वारा निर्धारित किया गया था, स्वीकारोक्ति करने के लिए एक प्रलोभन के बराबर नहीं था।

इसके अलावा, यह माना गया कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं हो सकता है कि वापस लिए गए स्वीकारोक्ति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि इसकी भौतिक रूप से पुष्टि नहीं की जाती है। लेकिन विवेक और सावधानी के मामले के रूप में, जिसने खुद को कानून के शासन में पवित्र कर लिया है, एक वापस ली गई स्वीकारोक्ति को केवल दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में स्वीकारोक्ति में उल्लिखित प्रत्येक परिस्थिति की अलग से और

स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहिए, और न ही यह आवश्यक है कि पुष्टि स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद खोजे गए तथ्यों और परिस्थितियों से होनी चाहिए। यह पर्याप्त होगा यदि स्वीकारोक्ति की सामान्य प्रवृत्ति को कुछ सबूतों द्वारा प्रमाणित किया जाता है जो स्वीकारोक्ति में निहित है। तत्काल मामले में मानव रक्त से सना कपड़ों की बरामदगी, जिसके लिए अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, स्वीकारोक्ति की पर्याप्त पुष्टि थी।

बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. एल. आर. (1957) एस. सी. 216 पर भरोसा किया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील, 1957 की सं. 127।

1956 की आपराधिक अपील संख्या 728 और 1956 की संदर्भित सुनवाई संख्या 144 में मद्रास उच्च न्यायालय के 12 फरवरी, 1957 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील, 1956 की एस. सी. संख्या 120 और 135 में कोयंबटूर डिवीजन के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के 23 अक्टूबर, 1956 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई।

अपीलार्थी की ओर से एच. जे. उमरीगर और टी. एस. वेंकटरमन।

प्रतिवादी के लिए पी. रामा रेड्डी और टी. एम. सेन।

1957 में 17 सितंबर को न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश गोविंदा मेनन द्वारा दिया गया था।-कोयंबटूर डिवीजन के सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष चार आरोपी थे, जिनमें से पहले आरोपी सुब्रमण्यम गौंडन ने अब मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि के खिलाफ इस अदालत में अपील की है, जिसके द्वारा उन्हें 1 और 2 के आरोपों पर मौत की सजा सुनाई गई थी, और आरोप संख्या 3 पर दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। 6 मई, 1957 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी के साथ तीन अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से दूसरा अभियुक्त (मारप्पा गौंडन) उसके पिता थे, तीसरा अभियुक्त (करुप्पा) दूसरे अभियुक्त के पैतृक चाचा का पोता था, जबकि चौथा अभियुक्त (इयावु) दूसरे अभियुक्त के चौथे दर्जे में एक अगनेट था। इस प्रकार यह देखा जाता है कि सभी आरोपी एक-दूसरे के रिश्तेदार थे।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने चार आरोप तय किए जिनमें से पहला अपीलार्थी के खिलाफ था, कि उसने 6 जून, 1956 की रात को वेंगकलपालयम गाँव में मरप्पा गौंडन की एक अरुवल से काटकर हत्या की, जबकि दूसरा आरोप था कि लगभग उसी समय और स्थान पर और उसी लेन-देन के दौरान, उसने मुथु गौंडन की हत्या को भाले से चाकू मारकर किया। आरोप की तीसरी गिनती पहले और दूसरे आरोपी के खिलाफ थी कि उन्होंने एक मुनिया गौंडन को भाले और चाकू से चाकू मारकर हत्या के प्रयास का अपराध किया था, और आरोप की अंतिम गिनती आरोपी संख्या 3 और 4 के खिलाफ थी कि उन्होंने घटनास्थल पर उपस्थित होकर मुनिया गौंडन की हत्या के प्रयास के अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त संख्या 2,3 और 4 को बरी कर दिया, लेकिन दोषी ठहराया और हमारे सामने अपीलार्थी को ऊपर बताए गए तरीके से सजा सुनाई।
जिस गाँव में अपराध किए गए थे, वह गुट-बद्ध था जिसमें अपीलार्थी, उसके पिता और अन्य लोगों ने एक पक्ष लिया, जबकि दो मृत व्यक्तियों ने मुनिया गौंडन और अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रतिद्वंद्वी गुट के नेताओं का गठन किया। यह भी कहा गया था कि अपीलार्थी के पिता गाँव के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें गाँव वालों की सहमति से वह गरिमा सौंपी गई थी।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी के परिवार की गरिमा प्रतिद्वंद्वी पक्ष के कुछ कार्यों से आहत हुई थी और अपीलार्थी के पिता को यह आशंका थी कि गाँव के मुखिया के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा था और प्रतिद्वंद्वी समूह द्वारा हड़पा जा रहा था। कहा जाता है कि घटना से लगभग तीन दिन पहले, जो 6 और 7 जून, 1956 की रात को हुई थी, मुनिया गौंडन ने अपीलार्थी की सुनवाई में कहा था कि वह (मुनिया गौंडन) अपीलार्थी के पिता और उनके पक्षपातियों को मिटा देगा, और यदि यह संभव नहीं था, तो अपमान की भावना से, मुनिया गौंडन अपनी मूंछ मुंडवा दे। यह भी आरोप लगाया जाता है कि दोनों मृतक व्यक्तियों ने भी इस आशय के शब्दों की घोषणा की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपने परिवार के उन्मूलन की इस धमकी से क्रोधित और पहले से मौजूद गुट के कारण शत्रुता से उत्तेजित होकर, अपीलार्थी ने 6 और 7 जून, 1956 की रात को अपने घर से एक अरवल (एक दरांती), एक भाला और एक चाकू से लैस होकर, चेट्टीथोट्टम के नाम से जानी जाने वाली जगह पर आगे बढ़ा,

जहां मृतक मारप्पा गौंडन अपने खेत में सो रहा था, और उसे अरवल से गर्दन पर काट दिया, और उस जगह से जाने से पहले उस पर अन्य चोटें लगा दीं। इसके बाद जब वह मुनिया गौंडन को हटाने के लिए उसके घर जा रहा था, तो अपीलकर्ता मृतक मुथु गौंडन से मिला, जो विपरीत दिशा से आ रहा था और यह सोच रहा था कि मुथु गौंडन उसे पकड़ लेगा, और मुथु गौंडन को चाकू से घायल कर दिया। इसके बाद अपीलार्थी मुनिया गौंडन (पी. डब्ल्यू. 5) के घर गया और उसे भी चाकू मार दिया। इन अपराधों को करने से संतुष्ट नहीं होने के कारण, उसने सेन्निमलाई गौंडन (पी. डब्ल्यू. 4-जो प्रतिद्वंद्वी गुट का पक्षपाती भी था) के शेड में आग लगा दी, जो गाँव से लगभग चार फ़र्लांन्ग की दूरी पर था। इसके बाद अपीलार्थी अपने बगीचे में लौट आया और लेट गया।

करुप्पा गौंडन (पीडब्लू. 1) ने मुनिया गौंडन के घर की ओर से चिल्लाने और चिल्लाने की आवाज सुनी, वह उस जगह की ओर भागा, उसके बाद सेन्निमलई गौंडन-(पीडब्लू. 4) ने भी वही चिल्लाने की आवाज सुनी। उन्होंने मुनिया गौंडन (पी. डब्ल्यू. 5) को चोटों के साथ पाया और सेन्निमलई गौंडन (पी. डब्ल्यू. 4) के शेड को भी देखा। इस पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 जलते हुए शेड की ओर बढ़े और रास्ते में मृत मरप्पा गौंडन के बेटे नटराजन (P.W.10) को अपने खेत में रोते और विलाप करते हुए देखा। जिस स्थान से पीडब्लू 10 रो रहा था, उस स्थान पर पहुंचने पर पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 ने मारप्पा गौंडन को शेड में एक खाट पर घायल अवस्था में मृत पड़ा देखा। यह सबूत है कि गवाहों ने तब पी. डब्ल्यू. 4 का शेड पूरी तरह से जलता हुआ देखा और उसके बाद करुप्पा गौंडन और सेन्निमलाई गौंडन गाँव से लगभग चार मील दूर रहने वाले गाँव मुन्सिफ़ के घर गए और 7-6-1956 पर सुबह लगभग 5 बजे घटना के बारे में एक रिपोर्ट दी और जो प्रदर्शनी पी. 1 के रूप में दर्ज है। सूचना अवनाशी के पुलिस उप-निरीक्षक (पीडब्लू 17) तक सुबह 8-30 पर पहुंची जो सुबह 11 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद जांच शुरू की गई, जिसके विवरण का उल्लेख करना अनावश्यक है। दोपहर लगभग 12 बजे गाँव के एक मंदिर के पास पुलिस उप निरीक्षक ने अपीलार्थी को वहाँ पाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अपीलार्थी ने एक बयान दिया जिसके स्वीकार्य भागों को प्रदर्शनी पी. 13 के रूप में चिह्नित किया गया है। अपीलार्थी की सामग्री वस्तुओं संख्या 10 और 11 से, उसके द्वारा पहने गए क्रमशः एक रक्तरंजित दराज और एक बनियान को जब्त कर लिया गया और इसके बाद अपीलार्थी पुलिस

अधिकारी को अपने बगीचे में ले गया और बगीचे के शेड में एक राफ्टर से एम. ओ. 12, एक रक्तरंजित चादर निकाल ली, जिसका अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा अपराध करने के बाद अपने शेड में लेटने के बाद खुद को लपेटने के लिए उपयोग किया गया था। उप-निरीक्षक द्वारा कई व्यक्तियों से बयान लिए गए, जिनमें मारप्पा गौंडन के पुत्र नटराजन (पीडब्ल्यू 10), मुथु गौंडन के पुत्र नचिमुथु गौंडन (पीडब्ल्यू 11), मुनिया गौंडन (पीडब्ल्यू 5) और अन्य शामिल थे। हम बरी किए गए व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों के संबंध में जांच और गवाहों से पूछताछ के विवरण का वर्णन करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

9 जून, 1956 को लगभग 1 बजे अपीलार्थी को श्री पी. आई. वीरास्वामी, उप-मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू. 7) के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आपराधिक व्यवहार नियमों के तहत आवश्यक चेतावनी दी और इस बात से संतुष्ट होकर कि अपीलार्थी स्वैच्छिक बयान देना चाहता है, उसे 11 जून, 1956 तक विचार के लिए दो दिन का समय दिया गया, जिस तारीख को अपीलार्थी को उसी मजिस्ट्रेट के सामने 1 बजे पेश किया गया था। वही चेतावनियाँ उन्हें फिर से दी गईं और मजिस्ट्रेट संतुष्ट थे कि जो बयान दिया जाना था वह स्वैच्छिक था। अपीलार्थी के अपने शब्दों में इसे दर्ज किए जाने के बाद, उसे पढ़ें और उसके द्वारा सही होने को स्वीकार करें। यह बयान जिसमें अपीलार्थी ने मरप्पा गौंडन और मुथु गौंडन की हत्या करने और विचाराधीन रात को मुनिया गौंडन को घायल करने की बात स्वीकार की है, पी. 3/ए. के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

अपीलार्थी के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य निर्भरता नटराजन (पी. डब्ल्यू. 10) पर थी, जो अपने पिता मारप्पा गौंडन पर हमले के चश्मदीद गवाह थे, और मुथु गौंडन की हत्या के संबंध में, मामला मुथु गौंडन के बेटे नचिमुथु गौंडन (पी. डब्ल्यू. 11) की गवाही पर आधारित था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने गवाह (पी. डब्ल्यू. 12) को बताया था कि अपीलार्थी ने मुथु को भाले से चाकू मारा था। मुथु गौंडन के पड़ोसी सुब्बन्ना गौंडन (पीडब्लू 12) ने भी इस तथ्य पर बात की कि उसने मुथु गौंडन को यह कहते हुए सुना कि अपीलार्थी ने उसे भाले से वार किया था। मुनिया गौंडन (पी. डब्ल्यू. 5) पर हमले की बात खुद से कही जाती है। इस साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को अपीलार्थी के इकबालिया बयान पर रोक दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी ने अपराध से

इनकार किया और इस आधार पर अपने द्वारा किए गए इकबालिया बयान को वापस ले लिया कि उप-निरीक्षक और पुलिस के सर्कल निरीक्षक ने अपीलार्थी के पिता और पांच अन्य लोगों को अपराध में फंसाने की धमकी दी यदि वह कबूल नहीं करता है और यही कारण था कि उसने झूठा इकबालिया बयान दिया।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने हत्याओं के संबंध में नटराजन (पीडब्ल्यू 10), नचिमुथु गौंडन (पीडब्ल्यू 11) और सुब्बन्ना गौंडन (पीडब्ल्यू 12) और मुनिया गौंडन (पीडब्ल्यू 5) और कोमारास्वामी गौंडन (पीडब्ल्यू 6) की गवाही को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी माना कि स्वीकारोक्ति, प्रदर्शनी पी. 3/ए स्वैच्छिक और सत्य थी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर, स्वीकारोक्ति द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई, अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सोमसुंदरम, जिन्होंने न्यायालय का निर्णय दिया, पी. डब्ल्यू. 5, पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 की मौखिक गवाही पर भरोसा करने के लिए इच्छुक नहीं थे। विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि नटराजन (पीडब्लू 10) के साक्ष्य पर कार्रवाई करना और अपीलार्थी को मारप्पा गौंडन की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं था। उच्च न्यायालय ने नचिमुथु गौंडन (पीडब्लू 11) और सुब्बन्ना गौंडन (पीडब्लू 12) के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि मुनिया गौंडन (पीडब्लू 5) और (पीडब्लू 6) कोमारस्वामी गौंडन के साक्ष्य पर कार्रवाई करना सुरक्षित नहीं है। निष्कर्ष यह था कि मौखिक साक्ष्य दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए निर्भरता के लिए आवश्यक प्रमाण के उस मानक तक नहीं पहुंचे, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा कि चूंकि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य थी, इसलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है, हालांकि उसे वापस ले लिया गया था। राय यह भी व्यक्त की गई कि स्वीकारोक्ति की पुष्टि एम. ओ. 12 की बरामदगी द्वारा की गई थी, जो अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान के परिणामस्वरूप थी जिसमें मानव-रक्त था जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। एम. ओ. पर मानव-रक्त के अस्तित्व द्वारा भी पुष्टि की गई थी। आई. ओ. और 11. इसलिए, हमारे सामने सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के अपराध के संबंध में निचली अदालत से सहमत होकर कानून में गलती की है।

क्या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि पीडब्ल्यू 5, 10 और 11 का साक्ष्य अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए स्वीकार

किया जा सकता है, प्रश्न का समाधान सरल होता और वैकल्पिक रूप से क्या यह न्यायालय उनकी गवाही की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए इच्छुक था या अन्यथा, क्या एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा जाता, यह अनुमान लगाना अनावश्यक है। इन गवाहों के साक्ष्य के अवलोकन पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी गवाही ऐसी है जिसे अविश्वास के दायरे में लाया जाना चाहिए। फिर भी, हमने इस आधार पर आगे बढ़ने का फैसला किया है कि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि अपीलार्थी उचित संदेह से परे दोषी है।

इसलिए, इस प्रश्न के लिए अंतिम दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या स्वीकारोक्ति, Ex पी. 3/ए. विश्वास करने और उस पर कार्रवाई करने का हकदार है। अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री उमरीगर, यह दिखाने के लिए दुखी थे, सबसे पहले कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं थी; दूसरा, यह सच और अंत में नहीं है कि जहां तक अभियोजन पक्ष का संबंध है, अगर इन दोनों परीक्षणों का जवाब सकारात्मक भी दिया जाता है, तो भी इस वापस लिए गए स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई करना बहुत असुरक्षित होगा, जिसे उनके अनुसार, अवसर मिलते ही वापस ले लिया गया था। पहले प्रश्न पर विचार करते हुए, उन्होंने बताया कि अपीलार्थी को 9 जून, 1956 को दोपहर 1 बजे अदालत कक्ष में उप-मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसे सभी पुलिस अधिकारियों से मुक्त कर दिया गया था और अकेले जेल वार्डर को प्रभारी बनाया गया था। इसके बाद उप-मजिस्ट्रेट ने आवश्यक चेतावनी दी और विचार के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अपीलार्थी के वकील द्वारा की गई आलोचना यह है कि इन लाभकारी कार्यों के बावजूद, अपीलार्थी पर पुलिस का प्रभाव अभी भी बना हुआ है और जब स्वीकारोक्ति दी गई थी, तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी पुलिस के दबाव से मुक्त था। पी. डब्ल्यू. 7 की प्रतिपरीक्षा के अंशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों अवसरों पर जब अपीलार्थी को स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए पेश किया गया था, तो उप-जेल में पहरा देने वाला पुलिस कांस्टेबल प्रभारी था और आगे यह कि पुलिस स्टेशन और अदालत के बीच एक प्रवेश द्वार है, और वह प्रवेश द्वार उप-जेल तक पहुंचने का मार्ग है। इन परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है कि हालांकि प्रासंगिक अवधि के दौरान अपीलार्थी का कारावास उप-जेल में था, फिर भी वह पुलिस हिरासत और प्रभाव में था और इसलिए, उस पर

पुलिस नियंत्रण की कोई मंजूरी नहीं थी, ताकि उसके दिमाग को ऐसे सभी प्रभावों से मुक्त किया जा सके। हमने मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा है, न केवल 9 जून, 1956 को, जब अपीलार्थी को विचार के लिए समय दिया गया था, बल्कि 11 जून, 1956 को भी, जब उसने इकबालिया बयान दिया था, और हम संतुष्ट हैं कि अपनाई गई प्रक्रिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की ss.164 और 364 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ कबूलनामे की रिकॉर्डिंग के लिए प्रारंभिक रूप से मद्रास आपराधिक व्यवहार नियमों में निर्धारित निर्देशों का पालन किया है। उप-मजिस्ट्रेट की अल्प प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई भौतिक परिस्थितियाँ सामने नहीं आई हैं जो किसी भी तरह से, अपने आधिकारिक कर्तव्य का संतोषजनक तरीके से पालन करने में बाधा उत्पन्न करें। इकबालिया बयान के आधार पर समर्थन में उप-मजिस्ट्रेट (पीडब्लू 7) का कहना है कि उन्होंने अपीलार्थी को समझाया था कि वह (अपीलार्थी) स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं था और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है। और समर्थन आगे यह जोड़ता है कि उप-मजिस्ट्रेट का मानना था कि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की गई थी। अगली टिप्पणी यह है कि इसे उनकी उपस्थिति और सुनवाई में लिया गया और पढ़ा गया जिसने इसे सही माना। लेकिन स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति के खिलाफ यह आग्रह किया जाता है कि जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, उससे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रलोभन दिया गया था। उन प्रश्नों में से एक था 'आप बयान क्यों देना चाहते हैं?' और जवाब दिया गया था 'यह संदेह है कि जिन लोगों ने हत्या की है वे अन्य हैं। यह साबित करने के लिए कि मैंने ही चाकू मारा है, मैं बयान दे रहा हूं। उपरोक्त प्रश्न 9 जून, 1956 को रखा गया था और इसका उत्तर दिया गया था। 11 जून, 1956 को प्रश्न और उत्तर इस प्रकार थेः

"प्रश्न- आप किस उद्देश्य से बयान देने जा रहे हैं?

उ. हत्या के मामले में अन्य लोगों को फंसाया जाएगा, मैंने अकेले हत्या की है। मैं इस आशय का बयान देने जा रहा हूं "।

जब वह सत्र अदालत में स्वीकारोक्ति से मुकर गया, तो अपीलार्थी ने कहा कि उप-निरीक्षक और सर्कल इंस्पेक्टर उप-जेल में उसके पास गए और

उसके पिता, आरोपी नंबर 2 और पांच अन्य लोगों को निचली अदालत में फंसाने की धमकी दी, जब तक कि वह स्वीकार नहीं करता। इसलिए, यह इस कारण से था कि कथन एक्सपी; 3/ए मजिस्ट्रेट के समक्ष बनाया गया था जो आरोपी ने आरोप लगाया था कि न तो सच था और न ही स्वैच्छिक था। विद्वान वकील का तर्क है कि अपने पिता और कुछ अन्य लोगों को बचाने के लिए, अपीलार्थी ने खुद को फंसाया और एक ऐसे कार्य को गलत तरीके से स्वीकार किया जो उसने नहीं किया था। जिस तरीके और तरीके से सवाल उठाया गया था, उसके खिलाफ आलोचना की गई है क्योंकि यह सीधे तौर पर अपीलार्थी को आत्मदाह करने के लिए प्रेरित करता है और इस तरह अपने रिश्तेदारों को बचाता है। हमें यह कहने के लिए कहा जाता है कि अपीलार्थी, महान भावनाओं और भावनाओं वाला एक भावुक युवक होने के नाते, अपने पिता को इस तरह के अपराध में फंसाना नहीं चाहता था और अपने पिता को पुलिस के जाल से मुक्त कराने की कोशिश में एक पारिवारिक दायित्व के रूप में वर्णित किया जा सकता था। हमें डर है कि इस तरह के तर्क से कोई विश्वास नहीं हो सकता है। प्रश्न का रूप आपराधिक अभ्यास नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है और यदि वह अधिकारी जिसके समक्ष स्वीकारोक्ति की गई है, उसे रखने में विफल रहता है, तो उसकी विफलता की आलोचना की जाएगी। हम यह नहीं महसूस करते हैं कि अपीलार्थी से यह पूछने के लिए कि "वह बयान क्यों देना चाहता है?" एक पूरी तरह से हानिरहित और अनिवार्य प्रश्न पूछने में कोई नापाक उद्देश्य मौजूद था। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 17, जांच उप-निरीक्षक, ने पुलिस द्वारा कथित प्रलोभन से स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि अगर वह कबूल नहीं करता है, तो उसके पिता सहित अन्य लोगों को मामले में फंसाया जाएगा। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी थी जिसके परिणामस्वरूप एक अनैच्छिक स्वीकारोक्ति की गई थी।

विद्वान वकील द्वारा एक शिकायत की जाती है कि दंडनीय मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 342 के तहत कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। स्वीकारोक्ति के संबंध में अपीलार्थी के समक्ष रखा गया था और इसलिए, जब तक मामला सत्र अदालत के समक्ष नहीं आता, तब तक उसे स्वीकारोक्ति के बारे में अपनी शिकायत रखने का कोई अवसर नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उप-मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के बयान की जांच से कोई विशिष्ट प्रश्न प्रकट नहीं होता है जैसा कि उसे स्वीकारोक्ति के बारे में

पूछा गया था, लेकिन तथ्य यह है कि स्वीकारोक्ति को प्रतिबद्ध अदालत के समक्ष प्रदर्शित किया गया था और सामग्री अपीलार्थी को तब और वहाँ ज्ञात थी। धारा 207-ए, उप-क्ल के तहत दंड प्रक्रिया संहिता के (3) सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य किसी मामले की जांच शुरू होने पर भी, जब अभियुक्त को उसके सामने लाया जाता है, तो उसे यह संतुष्ट करने का आदेश दिया जाता है कि धारा 173 में उल्लिखित दस्तावेज अभियुक्त को प्रस्तुत किए गए हैं और यदि यह पाया जाता है कि वे अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह उन्हें प्रस्तुत करे। धारा 173, उप-क्ल(4) पुलिस पर यह अनिवार्य बनाता है कि वह अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट, एफ. आई. आर. की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करे। धारा 154 के तहत और अन्य सभी दस्तावेज जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान और स्वीकारोक्ति शामिल हैं। इसलिए, परिणाम यह है कि प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू होने से पहले ही, अपीलार्थी को उस इकबालिया बयान की प्रति प्रदान की गई थी जिस पर उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले को उचित ठहराने के लिए भरोसा किया जाना चाहिए था। हमें नहीं लगता कि यह स्वीकार करते हुए कि स्वीकारोक्ति को प्रतिबद्ध न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में सामने नहीं रखा गया था, इस तरह की चूक यदि एक है, तो यह किसी भी तरह से दिखाएगा कि स्वीकारोक्ति अनैच्छिक थी।

विद्वान वकील के तर्क का दूसरा पहलू यह है कि स्वीकारोक्ति सच नहीं है। सरवन सिंह और हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य (') में इस अदालत ने यह राय व्यक्त की कि यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या एक स्वीकारोक्ति सच है, इसकी जांच करना और अभियोजन पक्ष के बाकी साक्ष्य और मामले की संभावनाओं के साथ इसकी तुलना करना आवश्यक होगा, और श्री उमरीगर इन टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए आग्रह करते हैं कि स्वीकारोक्ति की अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अन्य हिस्सों के साथ तुलना करने पर, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होना चाहिए कि इसके सामने इकबालिया बयान असत्य है। वास्तविक अपराध से संबंधित इकबालिया दस्तावेज़ के भौतिक भाग निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

"इसलिए, बुधवार की रात लगभग 11 बजे, मैं दोनों तरफ से अरुवल, भाला और चाकू लेकर अपने बगीचे के पास चेट्टी थोट्टम गया। मरप्पा गौंडन, तब अपने शेड में खाट पर लेटा हुआ था और सो रहा था। मैंने उसे गर्दन पर अरवल से काट दिया। वहाँ से आते हुए, हमारे गाँव में

मुनियप्पा गौंडन के घर, मुथु गौंडन हमारे गाँव की गली में मेरे सामने आया। यह सोचकर कि वह मुझे पकड़ने आया है, मैंने उसे चाकू मार दिया। अरुवल वहीं गिर गया।
फिर, मैं मुनियप्पा गौंडन के घर गया और मुनियप्पा गौंडन को चाकू मार दिया।
इसके बाद, मैंने अपने गाँव से चार फरलोंग की दूरी पर सेन्निमलाई गौंडन के शेड में आग लगा दी। फिर मैं अपने बगीचे में आया और लेट गया।

इससे बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, यह देखा गया है कि मरप्पा गौंडन की गर्दन पर केवल एक कट लगाया गया था और मुथु गौंडन को एक छुरा मारा गया था। इसी तरह मुनिया गौंडन को केवल एक बार चाकू मारा गया था, लेकिन एक्स पी. 4 मे मरप्पा गौंडन के शरीर पर पोस्टमॉर्टम प्रमाण पत्र में तेरह चोटें हैं जिनमें से गर्दन की चोटें 4,5 और 6 थीं, अन्य शरीर के अन्य हिस्सों पर थीं। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि मारप्पा, कई चोटों के अस्तित्व का निर्विवाद तथ्य स्वीकारोक्ति की सच्चाई को नकारता है, जिसमें गर्दन पर केवल एक कट दिया गया था। इसी तरह जब मुनिया गौंडन को चाकू मारा गया था तो स्वीकारोक्ति में किसी और की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि पी. डब्ल्यू. 5 और पी. डब्ल्यू. 6 दोनों ने अपदस्थ किया है कि तीन व्यक्ति थे जो उस समय मरप्पा गौंडन के शेड से उत्तर की ओर आ रहे थे जब पी. डब्ल्यू. 5 को चाकू मारा गया था। पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा दिया गया बयान (उदा. डी. 2) 8 जून, 1956 को चिकित्सा अधिकारी के समक्ष यह भी प्रभाव था कि उन पर हमले में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। स्वीकारोक्ति में अपीलार्थी द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान के परिणामस्वरूप एम. ओ. 12 जैसे आपत्तिजनक लेखों की बरामदगी का भी कोई संदर्भ नहीं है। इन परिस्थितियों से हमें यह कहने के लिए कहा जाता है कि स्वीकारोक्ति सच नहीं हो सकती है। श्री उमरीगर आग्रह करते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इस अदालत द्वारा निर्धारित परीक्षण के अनुसार मामले में अन्य साक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करके यह जांचने की इस विधि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है कि कब तक एक स्वीकारोक्ति सच है। उच्च न्यायालय के निर्णय में इस तरह की तुलना के अभाव में भी हम नहीं सोचते हैं कि उस आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से गलत बयान दिया है। आखिरकार स्वीकारोक्ति में विस्तृत विवरण की

अनुपस्थिति इसे गलत नहीं बता सकती है। स्वीकारोक्ति में ऐसा कोई बयान नहीं है जो मौखिक साक्ष्य के विपरीत हो, हालांकि जब अदालत में गवाहों से पूछताछ की गई थी तो सामने रखा गया विवरण स्वीकारोक्ति में विस्तार से दिखाई नहीं देता है और इस कारण से हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि स्वीकारोक्ति असत्य है।

अगला सवाल यह है कि क्या स्वीकारोक्ति की पुष्टि हुई है क्योंकि इसे वापस ले लिया गया है। एक व्यक्ति द्वारा अपराध का स्वीकारोक्ति, जिसने इसे किया है, आमतौर पर पश्चाताप का परिणाम होता है और सामान्य परिस्थितियों में निर्माता के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत होता है। यह सवाल बहुत बार उठा है कि क्या एक वापस लिया गया स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि का आधार बन सकता है यदि माना जाता है कि यह सच है और स्वेच्छा से किया गया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से अदालत को न केवल स्वीकारोक्ति करने या इसे वापस लेने के लिए दिए गए कारणों पर ध्यान देना होगा, बल्कि इसके आसपास के उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर भी विचार करना होगा। यह टिप्पणी की जा सकती है कि कोई पूर्ण नियम नहीं हो सकता है कि वापस लिए गए स्वीकारोक्ति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि इसकी भौतिक रूप से पुष्टि नहीं की जाती है। कुछ मामलों में यह निर्धारित किया गया था कि इनमें से एक केसवा पिल्लई उर्फ कोरालन और दूसरा केसवा पिल्लई उर्फ थिल्लई पिल्लई (') हैं कि यदि किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा स्वीकारोक्ति वापस लेने के लिए दिए गए कारण उनके सामने झूठे हैं, तो स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है जैसा कि यह है और बिना किसी पुष्टि के लेकिन इस अदालत द्वारा एक से अधिक अवसरों पर लिया गया विचार यह है कि विवेक और सावधानी के मामले के रूप में जिसने खुद को कानून के शासन में पवित्र कर लिया है, वापस लिए गए स्वीकारोक्ति को केवल दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि नवीनतम मामलों में से एक की पुष्टि नहीं की जाती है जो कि' पंजाब राज्य के बीर सिंह बनाम '(2) है, लेकिन इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि इसमें उल्लिखित प्रत्येक और हर परिस्थिति में दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। यह पर्याप्त होगा, हमारी राय में, कि स्वीकारोक्ति की सामान्य प्रवृत्ति कुछ सबूतों से प्रमाणित होती है जो स्वीकारोक्ति में निहित है। इस संबंध में एक वापस ली गई स्वीकारोक्ति की तुलना एक सरकारी गवाह या एक सहयोगी के साक्ष्य से करना लाभदायक होगा। यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के तहत एक दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह गवाहों की अप्रमाणित

गवाही पर आगे बढ़ती है, चित्रण (बी) से धारा 114 में कहा गया है कि एक अदालत यह मान सकती है कि एक साथी श्रेय के योग्य नहीं है जब तक कि उसकी भौतिक विवरणों में पुष्टि नहीं की जाती है। ऐसे व्यक्ति के मामले में अपने दम पर वह एक भ्रष्ट और अपमानित व्यक्ति है जो अपराध में भाग लेने के बाद खुद को दोषमुक्त करने की कोशिश करता है और दूसरे पर दायित्व को बढ़ाना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में यह बिल्कुल आवश्यक है कि उसने जो पदच्युत किया है उसकी भौतिक विवरणों में पुष्टि की जानी चाहिए। इसे स्वीकारोक्ति देने वाले व्यक्ति के बयान के विपरीत, जो एक बेहतर आधार पर खड़ा है, किसी को केवल तभी पता लगाने की आवश्यकता होती है जब एक वापसी होती है कि क्या पहले का बयान, जो पश्चाताप का परिणाम था, स्वैच्छिक था और सच था या नहीं और इसी उद्देश्य के साथ पुष्टि की जाती है। कभी-कभी कोई व्यक्ति किसी सहयोगी के साक्ष्य के साथ वापस लिए गए स्वीकारोक्ति की तुलना करने में गलती करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है और इसलिए, दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने की सलाह दी जाती है। दोनों में पुष्टि के मानक काफी अलग हैं। उस व्यक्ति के मामले में जो स्वीकार करता है कि जिसने अपने बयान से पलटवार किया है, सामान्य पुष्टि पर्याप्त है जबकि एक सहयोगी के साक्ष्य की भौतिक विवरणों में पुष्टि की जानी चाहिए। इसके अलावा, अदालत को यह महसूस करना चाहिए कि स्वीकारोक्ति के मामले में वापस लेने के लिए दिए गए कारण असत्य हैं।

वर्तमान मामले में इस परीक्षण को लागू करते हुए, हमारी राय है कि जब अपीलार्थी ने भौतिक वस्तुओं संख्या 10,11 और 12 पर मानव-रक्त की उपस्थिति के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो यह पता चलता है कि मारे गए व्यक्ति का रक्त इन भौतिक वस्तुओं पर था। पीछे हटने के कारण भी गलत हैं। एक आलोचना की जाती है कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में एम. ओ .12, बेड-शीट पर रक्त की सीमा नहीं दिखाई देती है, जिसमें अपीलार्थी ने अपराध के बाद खुद को लपेटा था। दस्तावेज़ में केवल इतना कहा गया है कि अन्य वस्तुओं के अलावा यह मानव रक्त से भी सना हुआ है, लेकिन श्री उमरीगर का तर्क है कि इस विवरण से केवल यह पता चलता है कि चादर पर केवल एक धब्बा या रक्त का धब्बा होता, क्योंकि उनके अनुसार, वास्तव में, अपीलार्थी के हाथों पर बड़ी मात्रा में रक्त होना चाहिए था, अगर उसने बिना धोए, चादर का उपयोग किया होता, तो बिस्तर पर रक्त के बड़े धब्बे होने की संभावना होती है। यदि ऐसा है, तो केवल यह तथ्य कि रक्त की

उपस्थिति को दाग के रूप में वर्णित किया गया है, यह दिखाएगा कि अभियोजन पक्ष का मामला सच नहीं हो सकता है। हम 'दाग' शब्द पर इस तरह का सीमित अर्थ डालने के लिए इच्छुक नहीं हैं। 'मानव रक्त के साथ निहित' एक अभिव्यक्ति है जो आमतौर पर रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में पाई जाती है और यह जरूरी नहीं कि केवल रक्त के धब्बों को संदर्भित करे। हमें नहीं लगता कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में 'दाग' शब्द के उपयोग से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि चादर पर पर्याप्त रक्त नहीं था। अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि भौतिक वस्तुओं संख्या 10 से 12 पर रक्त कैसे मौजूद हुआ। उच्च न्यायालय से सहमति जताते हुए कि यह अपीलार्थी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति की पुष्टि है, हमारी राय है कि स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि ऐसा है, तो अपीलार्थी का अपराध उचित संदेह से परे साबित हो गया है।

याचिका खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।